

कोलकाता में अमित शाह ने भरी हुंकार, ममता पर लगाया मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप

कोलकाता, 01 जून। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विजय संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन अधिनियम का 'विरोध' कर रही हैं। इसके अलावा, गृह मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुए दंगे 'राज्य प्रायोजित' थे। बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा,



'वोट बैंक के लिए ममता दीदी ने पतन की सीमा पार कर दी है। कुछ दिन पहले, पाक-प्रेरित आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिजनों के सामने मार दिया। इन आतंकियों को सजा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। पाक के अंदर घुसकर आतंकियों के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। आतंकियों की मौत पर दीदी को दर्द होता है। ममता बनर्जी ने घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया।' शाह ने कहा कि आपने (ममता बनर्जी) ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया है, आपने इस देश की करोड़ों

शाह ने दावा किया कि दंगों में टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया, 'मुर्शिदाबाद दंगे राज्य प्रायोजित थे। मुर्शिदाबाद दंगों के दौरान गृह मंत्रालय बीएसएफ की तैनाती पर जोर देता रहा, लेकिन टीएमसी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया, ताकि हिंसा जारी रहे। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गृह मंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी की भी आलोचना की।



नई दिल्ली, 01 जून। भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3,000 को पार कर गई है, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली नवीनतम लहर में सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, देश में वर्तमान में 3,395 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से केरल में सबसे अधिक 1,336 मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 467 और अन्य राज्यों में भी मामले बढ़ रहे हैं। केरल भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां शुक्रवार को 189 नए कोविड मामले दर्ज किए गए और वर्तमान में 1,336 सक्रिय संक्रमण हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (467), दिल्ली (375), गुजरात (265), कर्नाटक (234), पश्चिम बंगाल (205), तमिलनाडु (185)

मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई

नई दिल्ली, 01 जून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाव में हुए आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी पार्टी की मांग को एक बार फिर दोहराया है।



राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में चुप रहना चाहिए। इस बारे में बोलने से पहले यह समझना बेहतर है कि क्या हुआ है। प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट आने से पहले कोई चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी को

पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने इन घटनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए अपनी संसद का सत्र बुलाया है, और भारत को भी इस मामले में वैसी ही गंभीरता दिखानी चाहिए। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि पूरा देश सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता का आह्वान किया।

उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं से संयम बरतने और सैन्य कार्रवाई का राजनीतिकरण करने से बचने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'हमें पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। राष्ट्रीय मामलों में एकता होनी चाहिए और अपने विरोधियों को हराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश भर के सभी नेताओं को

चाहिए। सिद्धरमैया का यह बयान तटीय जिले दक्षिण कन्नड़ में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हत्याओं के मद्देनजर आया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बारे में सिद्धरमैया ने कहा कि कानून मंत्री एच. के. पाटिल और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खरे इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई और यदि कानून की आवश्यकता है, तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चर्चा के बाद वे जो सुझाव देंगे, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग क्रिकेट सट्टेबाजी का शिकार हो रहा है तथा जिलों में जुआ जैसी गतिविधियों पर सख्ती से नियंत्रण किया जाना चाहिए।

पूर्वांतर भारत में मानसूनी बारिश का कहर, 25 से अधिक लोगों की मौत, असम सबसे ज्यादा प्रभावित

असम, 01 जून। रविवार को अधिकारियों ने पुष्टि की कि पूर्वोत्तर भारत में लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण व्यापक भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। यहां हुए भूस्खलन के कारण कई घर मलबे में दब गए, जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह त्रासदी तब हुई जब भारी बारिश ने शहर को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया, जिससे पहाड़ियां और ढलानें अत्यधिक कमजोर पड़ गईं। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों को फिर से चेतावनी जारी की है और



सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। भूस्खलन के अलावा, राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ ने भी तीन और लोगों की जान ले ली। इनमें गोलाघाट जिले में दो और लखीमपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत शामिल है। यह प्राकृतिक आपदा पूर्वोत्तर भारत में मानसून के शुरूआती चरणों में ही एक गंभीर चुनौती बन गई है,

मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी आठ लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संख्या 17 हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये मौतें हुई हैं। मणिपुर में तीन दिनों से हो रही बारिश ने राजधानी इंफाल में दैनिक जीवन को ठप्प कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव की खबरें हैं, जिसके कारण अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निवासियों को निकालने का आग्रह किया है। उत्तर सिक्किम में लगभग 1,500 पर्यटक फंसे हुए हैं, क्योंकि भूस्खलन के कारण मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई है। इसके अलावा, मंगन जिले में

तीस्ता नदी में एक वाहन गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य लापता हो गए। भारतीय मौसम विभाग (वटऊ) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। असम के कुछ हिस्सों के लिए लाल और नारंगी अलर्ट जारी किए गए हैं, जबकि बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नारंगी और पीले अलर्ट जारी किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित असम में राहत और बचाव अभियान तेज हो गया है। उअमरु रउमरु पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की टीमों ने निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। दो जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहे और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन बाधित रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी राहत और बचाव अभियान चल रहा है।

नफरती बयानबाजी, ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर ही कर्नाटक सरकार: मुख्यमंत्री सिद्धरमैया

कर्नाटक, 01 जून। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार नफरती बयानबाजी के खिलाफ कानून बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कानून बनाने के बारे में चर्चा जारी है।



मुख्यमंत्री ने यहां सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और सभी जिला पंचायतों के सीईओ के साथ दो दिवसीय समीक्षा बैठक के अंत में यह बात कही। सिद्धरमैया ने कहा, मैंने कहा है कि अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इसके खिलाफ कानून लाएंगे। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, नफरत फैलाने वाले

मुख्यमंत्री ने यहां सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और सभी जिला पंचायतों के सीईओ के साथ दो दिवसीय समीक्षा बैठक के अंत में यह बात कही। सिद्धरमैया ने कहा, मैंने कहा है कि अगर कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम इसके खिलाफ कानून लाएंगे। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, नफरत फैलाने वाले

भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों। उनके खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज किए जाने

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है : जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 01 जून। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना केन्द्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। नड्डा यहां मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान



में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं, जिनसे निरामय राजस्थान की संकल्पना साकार होने लगी है।

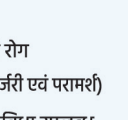
ट्रेन की चपेट में आने से मां-बेटे की मौत बहराइच। बहराइच जिले में बहराइच-गोंडा रेल प्रखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से मां-बेटे की मौत हो गयी। पुलिस क्षेत्राधिकारी पहलु सिंह ने रविवार को बताया कि शनिवार शाम रोशनी गुप्ता (25) अपने बेटे दिव्यांश (चार) के साथ बाजार गयी थी। लौटते वक्त वह बहराइच-गोंडा रेल प्रखंड के रेलवे पिलर संख्या 59/21 के निकट रेलवे लाइन पार करने के लिए खड़ी थी। उन्होंने बताया कि इसी बीच, बहराइच से गोंडा की ओर जा रही डेमो ट्रेन को देखकर बच्चा अपनी मां से हाथ छुड़ाकर रेलवे लाइन की तरफ भागा।



एपी मीडिया
हिन्दी दैनिक न्यूज पेपर, साप्ताहिक न्यूज पेपर, हिन्दी मासिक पत्रिका का पेज बनबाने के लिए सम्पर्क करें: 9199355950



डा. अरुण आर. सिंह
M.S.M.C.H.
गुर्गा एवं मृग रोग विशेषज्ञ (सर्जरी सर्जन)



डा० रवि प्रकाश सिंह
M.S. (Ortho)
हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ



डा० सुमित कुमार सिंह
M.D. (Neuro Psychiatrist)
मानसिक रोग विशेषज्ञ



डा० प्रभात सिंह
M.D. (Medicine)
कंसल्टेंट फिजिशियन



24/7 Emergency Services

वीमा कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध

आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधाएं

8090966086, 8090015086
कलीचाबाद, जौनपुर



मोहम्मद दानिश
जिला पंचायत सदस्य



वार्ड न० 10
के भावी प्रत्याशी

विकास खण्ड मोंधी शाहगंज जौनपुर

नक्सलवाद पर लगाम की ओर बढ़ते कदम

नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के संघर्ष में बीती 21 मई को नया इतिहास रचा गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अब्दुलमाइद के जंगल में सुरक्षा बलों ने सीपीआई (माओवादी) के महासचिव और सर्वोच्च कमांडर नाला केशव राव उर्फ बासवराजू को मार गिराया। उसके साथ 26 और नक्सली मारे गए। इसके कुछ दिन बाद झारखंड में भी तीन नक्सली मारे गए। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 के अंत तक नक्सलवाद के देश से सफाये का लक्ष्य रखा है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के लगातार कसते शिकंजे का संकेत भी कुछ ऐसा ही है।

नक्सलवाद के उभार के बाद से यह पहला मौका है, जब कोई सर्वोच्च नक्सली कमांडर और महासचिव स्तर का व्यक्ति मारा गया हो। गुहमंत्री अमित शाह ने इसे अपने बयान में रेखांकित भी किया। इस घटना के तुरंत बाद एकी बयान में अमित शाह ने इस मुठभेड़ को नक्सलवाद खत्म करने की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि बताने में हिचक नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ तीन दशकों की लड़ाई में महासचिव स्तर के नेता को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। केशव राव उर्फ बासवराजू को जिस ऑपरेशन के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस आे छत्तीसगढ़ पुलिस ने मार गिराया, उसे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम दिया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैले जंगलों में जारी इस ऑपरेशन



के तहत जहां 54 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं 84 नक्सलियों ने समर्पण किया है। जिस तरह धड़ाधड़ सफल मुठभेड़ हो रही है, नक्सली समर्पण कर रहे हैं या फिर गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उससे अमित शाह का उम्मीद रखना बेमानी भी नहीं है। मोदी सरकार ने साल 2014 में जब सत्ता संभाली थी, तब देश के 70 जिलों में नक्सलवाद का बड़ा असर था। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में नक्सलवाद पर लगाम को अपने प्रमुख कार्यक्रम में शामिल किया था। इसके एक साल पहले ही 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में राज्य कांग्रेस के तत्कालीन समूचे नेतृत्व को नक्सलियों ने निशाना बना दिया था। उससे उपजा क्षोभ ताजा था। वैसे भी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी माओवादी हिंसा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की हमेशा से पक्षधर रही है। कह सकते हैं कि इसी वजह से साल 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में नक्सलवाद पर लगाम को पार्टी ने अपना प्रमुख कार्यक्रम घोषित कर रखा था।

गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि नक्सलवाद का प्रभाव उन इलाकों में ज्यादा तेजी से बढ़ा, जहां जंगल थे, जहां आदिवासी समुदाय का निवास ज्यादा था, जहां शिक्षा का प्रचार कम था। यह सच है कि आधुनिक सभ्यता की सहयोगी आधुनिक व्यवस्था की निगाह जल-जंगल आदि प्राकृतिक संसाधनों के जरिए मुनाफाखोरी पर रही है। इस वैचारिकी का स्थानीय लोगों में प्रचार के जरिए मुनाफाखोरी ने अपनी गहरी पैठ बनाई। नक्सलवाद बुनियादी रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माओत्से तुंग की विचारधारा से प्रेरित है। जिनकी मा-यत्ता थी कि सत्ता बारूद से निकलती है। नक्सलवाद या माओवादी सोच के मूल में हिंसा की अवधारणा है। जिसके अनुसार बदलाव भी हिंसा के जरिए ही आता है। वैचारिकी तक अगर माओवाद सीमित रहता तो गनीमत थी। लेकिन माओवादी कमांडरों ने बाद में अपने प्रभाव बढ़ाते-बढ़ाते में अपनी ताकत का इस्तेमाल वसुली और मोटी कमाई के लिए करना शुरू कर दिया। तब से उनके प्रति समर्थन घटने लगा।

नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में अक्सर विकास के आधुनिक माध्यमों और प्रतीकों मसलन रेलवे लाइन, स्टेशन, डाकघर, स्कूल आदि को निशाना बनाते रहे। थोर-थोर उनके इस कृत्य को स्थानीय निवासी विकास विरोधी मानने लगे। जैसे-जैसे स्थानीय लोगों की यह समझ बढ़ी, नक्सलियों का समर्थक आधार कमजोर होता गया। उनके समर्थक आधार को कमजोर करने में उनके द्वारा व्यापक स्तर पर किए गए नरसंहारों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। झोरम घाटी के नक्सली हमले में जहां तीस से ज्यादा लोग मारे गए थे, 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के ताड़पेटला के जंगलों में नक्सलियों ने घात लगाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 75 और जिला बल के एक जवान को बारूदी सुरंग में उड़ा दिया था। इन हत्याओं के बाद नक्सली हिंसा को लेकर सवाल उठने लगा। नक्सलियों के समर्थक बौद्धिक तबके के लिए उनके बचाव में बोलना आसान नहीं रह गया। ताड़पेटला कांड के बाद तो उनके खिलाफ वायुसेना की कार्रवाई की मांग उठी थी, तब नक्सलियों के बौद्धिक समर्थकों ने इसका विरोध किया था। इस विरोध के चलते तत्कालीन मनमोहन सरकार ने नक्सली हिंसा को काबू करने के लिए सैनिक कार्रवाई को टाल दिया था।

मोदी सरकार की नजर में माओवादी हिंसा आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थी। वैसे मोदी सरकार को पता था कि नक्सलियों पर ऐसी कार्रवाई का एक बड़ा बौद्धिक वर्ग विरोध करेगा। इसलिए नक्सली हिंसा पर लगाम के लिए दोतरफा कार्रवाई शुरू की। एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों के बीच तालमेल बढ़ाने और नक्सल विरोधी खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ समावेशी विकास का पहिया तेजी से दौड़ाने की कोशिश की गई। इसमें सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया। इस रणनीति के जरिए माओवादी आंदोलन को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने में कामयाबी मिली। इससे माओवादियों के हाथों होने वाली हिंसा में कमी आई। लोगों में भय का माहौल कम हुआ। इसके साथ ही माओवादी उग्रवाद से प्रभावित कई जिलों को मुखधारा में शामिल करने में तेजी आई। इसकी वजह से स्थानीय निवासी नक्सलवाद दूरवर्ती इलाकों एवं जनजातीय गांवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखने लगे। उन्हें यह भरोसा होने लगा कि माओवादी हिंसा और सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और डाक सेवाओं को उनके गांवों तक पहुंचाने से रोकती है। नक्सलियों के समर्पण और उसके बाद उनके पुनर्वास पर जोर दिया गया। उन्हें हिंसा छोड़ने के बाद मुखधारा में शामिल होने और सामान्य ज़िंदगी बिताने के लिए सरकारी स्तर पर मदद दी जाने लगी। इसके साथ ही भारत सरकार को यह से बुनियादी ढांचे की कमी दूर करने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष योजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता दी जा रही है। इसके तहत नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित और चिंतित करने वाले जिलों को 30 और 10 करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। इसके अलावा, जरूरत के मुताबिक, इन जिलों के लिए विशेष परियोजनाएं भी दी जा रही हैं। इसकी वजह से पिछले 10 वर्षों के दौरान, 8,000 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। इसका असर यह होगा कि माओवादियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई कहीं ज्यादा सटीक होगी। इसका असर भी अब दिखने लगा है। अब जहां खूंखार नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर समर्पण कर रहे हैं, वहीं जनजातीय इलाकों में नई सड़कें और रेल लाइनें बनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ 'खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा मार्ग' से बलौदा बाजार जैसे नए क्षेत्रों को सीधा रेल-संपर्क मिलने जा रहा है। इस इलाके में 278 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। माओवाद विरोधी कार्रवाई की कमान संभालने वाले केंद्रीय बलों के अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा सरकार ने उनके लिए मुफ्रीद माहौल मुहैया कराया है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार की हार के बाद सुरक्षा बलों के कुछ अधिकारियों का मानना था कि नई सरकार की नीति बदलेगी। इसकी वजह से स्थानीय पुलिस और प्रशासन माओवादी हिंसा के खिलाफ उनके कदमों के प्रति सहयोगी रुख रखेगा। नक्सलवाद पर नेकेल के उपायों का असर ही कहा जाएगा कि साल 2014 में जहां नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 70 थी, जो अब घटकर 38 रह गई है। नक्सलवाद खत्म हो, विकास की गाड़ी दौड़ती रहे, जब जनजातीय समूह के लोगों को भी विकास में भागीदार बनाया जाए, इससे शायद ही किसी को इनकार होगा। लेकिन साथ ही व्यवस्था को यह भी देखना होगा कि फिर ऐसे हालात न बनें, जिससे स्थानीय निवासियों को बरगलाना आसान हो और वे हथियार उठाने के लिए मजबूर हों।

- उमेश चतुर्वेदी

आखिरकार बांग्लादेश की कमजोर नसों को कब दबाएगा भारत?

कभी 'ग्रेटर बंगलादेश' का स्वप्न संजोने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस अब अपने ही देश में ऐसे घिरें हैं कि जब उन्हें आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो फिर अपने जन्मदाता भारत पर ही अनर्गल लांचन लगाने लगे। वह अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की गोद में खेलें, कोई बात नहीं लेकिन भारत और हिंदुओं से खेलेंगे तो अगले ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार रहें। याद रखें, तब कोई बाप बचाने नहीं आएगा। हाल ही का पाकिस्तानी मंजर देख लें, अंजाम समझ लें और हो सके तो भारत के पड़ोस में बचकानी हरकत बंद कर दें।

बता दें कि अपनी पिछली चीन यात्रा के दौरान ही उन्होंने बढ़चढ़ कर रभारत के चिकेन नेकरज़ का काबिज होने, पश्चिम बंगाल-उत्तर-पूर्व बिहार और उत्तर-पूर्व के सात बहन राज्यों को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने और नार्थ-ईस्ट राज्यों को लैंड लॉकड बताकर इलाकाई समुद्र का बताज बादशाह होने का जो दिवास्वप्न उन्होंने देखा है, उसके मुताल्लिक भारत भी उन्हें दिन में ही तारे दिखाने की रणनीति बना चुका है। अब वो आगे बढ़ेंगे तो पीछे से भारत भी एक बार फिर बांग्लादेश का अंग भंग कर देगा! क्योंकि कभी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान का अंग भंग करवाकर भारत ने ही जिस बांग्लादेश की निर्माण करवाया था, आज वही बांग्लादेश जब भारत को आंखें दिखाएगा तो अपने अंजाम को भी भुगतने को तैयार रहेगा।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां की शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद महज 6 माह में ही परवर्ती कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस की अगुवाई में बांग्लादेश भारत विरोधी चीनी, पाकिस्तानी और अमेरिकी अखाड़े का अड्डा बन चुका है, जो उसके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। यही वजह है कि इस विफल सरकार के खिलाफ अब वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में युनुस ने अपना सारा दोष भारत पर मढ़ दिया है।

हालांकि भारत के पास उन्हीं जवाब देने के लिए ऐसे-ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जिससे उनके होश उड़ सकते हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश एक बार फिर से उबल रहा है, जिससे मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार अस्थिरता के बवंडर की ओर निरंतर बढ़ रही है। उनकी सेना से हठ उन्की ऊटपटांग नीतियों का विरोध हो रहा है। जबकि उनकी सरकार के खिलाफ जनता द्वारा भी अविलंब चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे मुल्क में तनाव का आलम व्याप्त हो चुका है। चूंकि इस विरोध प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो चुके हैं। इसलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू होते देख मोहम्मद यूनुस अपनी नाकामियों को बिना नाम लिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उनकी लापरवाही और अदूरदर्शिता से अब जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए 'विदेशी साजिश' को जिम्मेदार बता रहे हैं।

जबकि, हकीकत ये है कि उन्हें सिर्फ चुनाव करवाने तक के लिए सरकार चलाने भर की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन, जानकार बताते हैं कि वह चुनाव छोड़कर बाकी हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं। बांग्लादेश की विदेश नीति, उसका संविधान, उसका इतिहास और यहां तक कि उसके जन्म की मूल अवधारणा तक को वो नकारने के लिए आत्मघाती दांव लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेशी फौज भी उनके विरोध में खड़ी हुई है।

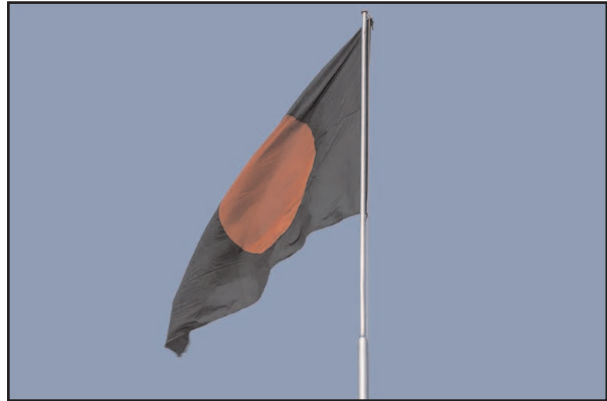
ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि मोहम्मद युनुस जब से बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं, भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के साथ झूम-झूम कर नाचने-गाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, उन्हें चीन के दम पर भारत के जिस भावुर के चिकन नेक कॉरिडोर (सिलीगुड़ी कांरिडोर) को दबा पाने की गलतफहमी हो गई है, ग्रेटर बांग्लादेश बनवाने में विदेशियों व भारत के मुसलमानों के साथ मिलने का भ्रम हो चुका है, और लैंड लॉकड नार्थ ईस्ट के चलते समुद्र का बताज बादशाह होने के जो सपने उन्होंने चीन को दिखाए हैं, तब उन्हें शायद यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भारत के रणनीतिकार उनके साथ और उनके हमदम चीन-पाकिस्तान-म्यांमार के साथ क्या क्या कर सकता है।

शायद मोहम्मद युनुस शायद यह भूल चुके हैं कि बांग्लादेश की पैदाइश ही कुशल भारतीय विदेश नीति की सफल देन रही है, जिसे तब अमेरिका व चीन नहीं रोक पाए थे। यह भारत की वीरता है जो चुटकड़ो पर युद्ध के मैदान में भारी पड़ती है। ऐसे में जब वो अपने जन्मदाता की संप्रभुता और अखंडता को ही चुनौती देने लगेंगे तो भारत को भी दर-सबेर अपने सटीक विकल्प तलाशने पड़ेंगे। यदि भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया सकेसाक्षात्कार को देखें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि नागपुर मुख्यालय से भी मोदी सरकार को उसी तरफ इशारा किया गया है। मसलन, संघ के मुखपत्र ऑनोर्नाइजर और पांचजन्य में गत रविवार को छपे उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने भारत के पड़ोस में 'बुराई को खत्म' करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करने की निर्माण करवाया था, आज वही बांग्लादेश जब भारत को आंखें दिखाएगा तो अपने अंजाम को भी भुगतने को तैयार रहेगा।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां की शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद महज 6 माह में ही परवर्ती कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस की अगुवाई में बांग्लादेश भारत विरोधी चीनी, पाकिस्तानी और अमेरिकी अखाड़े का अड्डा बन चुका है, जो उसके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। यही वजह है कि इस विफल सरकार के खिलाफ अब वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में युनुस ने अपना सारा दोष भारत पर मढ़ दिया है। हालांकि भारत के पास उन्हीं जवाब देने के लिए ऐसे-ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जिससे उनके होश उड़ सकते हैं।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश एक बार फिर से उबल रहा है, जिससे मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार अस्थिरता के बवंडर की ओर निरंतर बढ़ रही है। उनकी सेना से ही उनकी ऊटपटांग नीतियों का विरोध हो रहा है। जबकि उनकी सरकार के खिलाफ जनता द्वारा भी अविलंब चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे मुल्क में तनाव का आलम व्याप्त हो चुका है। चूंकि इस विरोध प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो चुके हैं। इसलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू होते देख मोहम्मद यूनुस अपनी नाकामियों को बिना नाम लिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उनकी लापरवाही और अदूरदर्शिता से अब जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए 'विदेशी साजिश' को जिम्मेदार बता रहे हैं।

जबकि, हकीकत ये है कि उन्हें सिर्फ चुनाव करवाने तक के लिए सरकार चलाने भर की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन, जानकार बताते हैं कि वह चुनाव छोड़कर बाकी हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं। बांग्लादेश की विदेश नीति, उसका संविधान, उसका इतिहास और यहां तक कि उसके जन्म की मूल



संप्रभुता की रक्षा के लिए जो तलख विचार सामने आ रहे हैं, उससे भारतीयों को यह आस्वस्त मिल रही है कि हमारा जवाब बहुत करारा होगा। क्योंकि रंगपुर में चिकन नेक कॉरिडोर काटने का मतलब है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही विशाल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह कि अभी जो लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है और जिसपर यूनुस और भारत के दुश्मनों की नजर लगी हुई है, वह अप्रत्याशित रूप से इतनी चौड़ी हो सकती है कि मतलब, पूर्वोत्तर की बहुत बड़ी समस्या एक ही झटके में खत्म हो सकती है।

वहीं, अगर हम त्रिपुरा के कुछ किलोमीटर तक नीच चले जाएं यानी चटगांव कॉरिडोर को भारत में मिला लें तो पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला भारत का अपना समुद्र यहां भी हो जाएगा। देखा जाए तो यह सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत ही फायदे का सौदा साबित होगा। क्योंकि भविष्य में मोहम्मद युनुस की तरह के विचार वाले बांग्लादेश के किसी अन्य शासक की भी आए तो आए दिन की होने वाली नौटंकी भी हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है।

इसके अलावा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के चटगांव से नीचे ही म्यांमार का रखाइन इलाका है, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की गम्भीर समस्या है। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश से चटगांव के कटते ही रोहिंग्या मुस्लिम समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि तब भारत इस इलाके को रोहिंग्या मुसलमानों को सौंप सकता है और भारत में जो रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उन्हें यहां पर स्थायी रूप से भेजा जा सकता है। क्योंकि यह उनका मूल इलाका है, जहां जाकर उनका उल्टे लिए भी आसान हो सकता है। इसके अलावा, म्यांमार के रखाइन से ही थोड़ा उत्तर-पूर्व में उसका और इलाका है, जो पहाड़ी क्षेत्र है और ईसाई (क्रिश्चियन) बहुल इलाका है, जो म्यांमार से अलग होना चाहता है। यह पहले से ही मिजोरम में मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यदि भारत ने इस पूरे इलाके पर दबदबा कायम कर लिया तो पूर्वोत्तर की कई उग्रवादी समस्याओं का हल निकालना भी आसान हो सकता है। क्योंकि, विदेश की यह धरती अभी उग्रवादियों के लिए नर्सरी का काम करती है, जिसे नियंत्रित करना और खत्म करना भारत के हित में है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1971 में भारत, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाकर एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में जन्म दे चुका है। इसलिए, ऊपर जो चार विकल्प दिए गए हैं, वह इसके लिए असंभव भी नहीं है। क्योंकि, मोहम्मद युनुस के कार्यकाल में जिस तरह से बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की ओर झुक गया है और वहां पर आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसके दृष्टिगत भारत के लिए इस वास्तविकता को ज्यादा लंबे समय तक टालना आसान नहीं है। इसलिए भारत अपने भविष्य को महफूज रखने की नीति अपनाए तो खुद पड़ोसियों को खण्ड-खंड करके कमजोर कर दे। पाकिस्तान-बांग्लादेश इसी के पात्र हैं और भारत को दृढ़तापूर्वक अपनी कार्रवाई व रणनीति को अंजाम देना चाहिए।

कभी 'ग्रेटर बांग्लादेश' का स्वप्न संजोने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस अब अपने ही देश में ऐसे घिरें हैं कि जब उन्हें आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो फिर अपने जन्मदाता भारत पर ही अनर्गल लांचन लगाने लगे। वह अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की गोद में खेलें, कोई बात नहीं लेकिन भारत और हिंदुओं से खेलेंगे तो अगले ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार रहें। याद रखें, तब कोई बाप बचाने नहीं आएगा। हाल ही का पाकिस्तानी मंजर देख लें, अंजाम समझ लें और हो सके तो भारत के पड़ोस में बचकानी हरकत बंद कर दें।

बता दें कि अपनी पिछली चीन यात्रा के दौरान ही उन्होंने बढ़चढ़ कर रभारत के चिकेन नेकरज़ पर युद्ध के मैदान में भारी पड़ती है। ऐसे में जब वो अपने जन्मदाता की संप्रभुता और अखंडता को ही चुनौती देने लगेंगे तो भारत को भी दर-सबेर अपने सटीक विकल्प तलाशने पड़ेंगे। यदि भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया सकेसाक्षात्कार को देखें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि नागपुर मुख्यालय से भी मोदी सरकार को उसी तरफ इशारा किया गया है।

मसलन, संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में गत रविवार को छपे उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने भारत के पड़ोस में 'बुराई को खत्म' करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करने की बात कही है, वह अब हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण ध्येय बनने जा रहा है। उनके अनुसार जिन कुछ देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदू समाज की ताकत का इस्तेमाल उनकी रक्षा के लिए किया जा चाहिए।

मसलन, संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में गत रविवार को छपे उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने भारत के पड़ोस में 'बुराई को खत्म' करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करने की बात कही है, वह अब हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण ध्येय बनने जा रहा है। उनके अनुसार जिन कुछ देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदू समाज की ताकत का इस्तेमाल उनकी रक्षा के लिए किया जा चाहिए।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहां की शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद महज 6 माह में ही परवर्ती कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस की अगुवाई में बांग्लादेश भारत विरोधी चीनी, पाकिस्तानी और अमेरिकी अखाड़े का अड्डा बन चुका है, जो उसके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। यही वजह है कि इस विफल सरकार के खिलाफ अब वहां भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में युनुस ने अपना सारा दोष भारत पर मढ़ दिया है। हालांकि भारत के पास उन्हीं जवाब देने के लिए ऐसे-ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जिससे उनके होश उड़ सकते हैं।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश एक बार फिर से उबल रहा है, जिससे मोहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार अस्थिरता के बवंडर की ओर निरंतर बढ़ रही है। उनकी सेना से ही उनकी ऊटपटांग नीतियों का विरोध हो रहा है। जबकि उनकी सरकार के खिलाफ जनता द्वारा भी अविलंब चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे मुल्क में तनाव का आलम व्याप्त हो चुका है। चूंकि इस विरोध प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो चुके हैं। इसलिए अपनी उल्टी गिनती शुरू होते देख मोहम्मद यूनुस अपनी नाकामियों को बिना नाम लिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वहां उनकी लापरवाही और अदूरदर्शिता से अब जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए 'विदेशी साजिश' को जिम्मेदार बता रहे हैं।

जबकि, हकीकत ये है कि उन्हें सिर्फ चुनाव करवाने तक के लिए सरकार चलाने भर की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन, जानकार बताते हैं कि वह चुनाव छोड़कर बाकी हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं। बांग्लादेश की विदेश नीति, उसका संविधान, उसका इतिहास और यहां तक कि उसके जन्म की मूल

अवधारणा तक को वो नकारने के लिए आत्मघाती दांव लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेशी फौज भी उनके विरोध में खड़ी हुई है। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि मोहम्मद युनुस जब से बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं, भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के साथ झूम-झूम कर नाचने-गाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, उन्हें चीन के दम पर भारत के जिस भावुर के चिकन नेक कॉरिडोर (सिलीगुड़ी कांरिडोर) को दबा पाने की गलतफहमी हो गई है, ग्रेटर बंग्लादेश बनवाने में विदेशियों व भारत के मुसलमानों के साथ मिलने का भ्रम हो चुका है, और लैंड लॉकड नार्थ ईस्ट के चलते समुद्र का बताज बादशाह होने के जो सपने उन्होंने चीन को दिखाए हैं, तब उन्हें शायद यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भारत के रणनीतिकार उनके साथ और उनके हमदम चीन-पाकिस्तान-म्यांमार के साथ क्या क्या कर सकता है। शायद मोहम्मद युनुस शायद यह भूल चुके हैं कि बांग्लादेश की पैदाइश ही कुशल भारतीय विदेश नीति की सफल देन रही है, जिसे तब अमेरिका व चीन नहीं रोक पाए थे। यह भारत की वीरता है जो चुटकड़ो पर युद्ध के मैदान में भारी पड़ती है। ऐसे में जब वो अपने जन्मदाता की संप्रभुता और अखंडता को ही चुनौती देने लगेंगे तो भारत को भी दर-सबेर अपने सटीक विकल्प तलाशने पड़ेंगे। यदि भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया सकेसाक्षात्कार को देखें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि नागपुर मुख्यालय से भी मोदी सरकार को उसी तरफ इशारा किया गया है।

मसलन, संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में गत रविवार को छपे उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने भारत के पड़ोस में 'बुराई को खत्म' करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करने की बात कही है, वह अब हमारी विदेश नीति का महत्वपूर्ण ध्येय बनने जा रहा है। उनके अनुसार जिन कुछ देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदू समाज की ताकत का इस्तेमाल उनकी रक्षा के लिए किया जा चाहिए।

इसके अलावा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के चटगांव से नीचे ही म्यांमार का रखाइन इलाका है, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की गम्भीर समस्या है। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश से चटगांव के कटते ही रोहिंग्या मुस्लिम समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि तब भारत इस इलाके को रोहिंग्या मुसलमानों को सौंप सकता है और भारत में जो रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उन्हें यहां पर स्थायी रूप से भेजा जा सकता है। क्योंकि यह उनका मूल इलाका है, जहां जाकर उनका उल्टे लिए भी आसान हो सकता है।

इसके अलावा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के चटगांव से नीचे ही म्यांमार का रखाइन इलाका है, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की गम्भीर समस्या है। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश से चटगांव के कटते ही रोहिंग्या मुस्लिम समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि तब भारत इस इलाके को रोहिंग्या मुसलमानों को सौंप सकता है और भारत में जो रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, उन्हें यहां पर स्थायी रूप से भेजा जा सकता है। क्योंकि यह उनका मूल इलाका है, जहां जाकर उनका उल्टे लिए भी आसान हो सकता है।

इसके अलावा, म्यांमार के रखाइन से ही थोड़ा उत्तर-पूर्व में उसका तिन इलाका है, जो पहाड़ी क्षेत्र है और ईसाई (क्रिश्चियन) बहुल इलाका है, जो म्यांमार से अलग होना चाहता है। यह पहले से ही मिजोरम में मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यदि भारत ने इस पूरे इलाके पर दबदबा कायम कर लिया तो पूर्वोत्तर की कई उग्रवादी समस्याओं का हल निकालना भी आसान हो सकता है। क्योंकि, विदेश की यह धरती अभी उग्रवादियों के लिए नर्सरी का काम करती है, जिसे नियंत्रित करना और खत्म करना भारत के हित में है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1971 में भारत, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाकर एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में जन्म दे चुका है। इसलिए, ऊपर जो चार विकल्प दिए गए हैं, वह इसके लिए असंभव भी नहीं है। क्योंकि, मोहम्मद युनुस के कार्यकाल में जिस तरह से बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की ओर झुक गया है और वहां पर आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसके दृष्टिगत भारत के लिए इस वास्तविकता को ज्यादा लंबे समय तक टालना आसान नहीं है। इसलिए भारत अपने भविष्य को महफूज रखने की नीति अपनाए तो खुद पड़ोसियों को खण्ड-खंड करके कमजोर कर दे। पाकिस्तान-बांग्लादेश इसी के पात्र हैं और भारत को दृढ़तापूर्वक अपनी कार्रवाई व रणनीति को अंजाम देना चाहिए।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1971 में भारत, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाकर एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में जन्म दे चुका है। इसलिए, ऊपर जो चार विकल्प दिए गए हैं, वह इसके लिए असंभव भी नहीं है। क्योंकि, मोहम्मद युनुस के कार्यकाल में जिस तरह से बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की ओर झुक गया है और वहां पर आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसके दृष्टिगत भारत के लिए इस वास्तविकता को ज्यादा लंबे समय तक टालना आसान नहीं है। इसलिए भारत अपने भविष्य को महफूज रखने की नीति अपनाए तो खुद पड़ोसियों को खण्ड-खंड करके कमजोर कर दे। पाकिस्तान-बांग्लादेश इसी के पात्र हैं और भारत को दृढ़तापूर्वक अपनी कार्रवाई व रणनीति को अंजाम देना चाहिए।

- कमलेश पांडेय

किसी न किसी प्रंगल से प्राणों की रक्षा की जाये। इधर भगवान शंकर, आज की तिथि में केवल भगवान ही नहीं हैं, अपितु मैना के जमाई भी हैं। किसी दूल्हे के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार हो जाये, तो निश्चित ही दूल्हा उस चौखट से वापिस मुड़ दूल्हा होता है। किंतु भगवान शंकर को देखिए, तो वे रती भर भी क्रोधित नहीं होते। वे स्वयं ही उस दिशा में बढ़ जाते हैं, जहाँ जनवास में उनके ठहरने का प्रबंध हुआ था। उन्हें तो महसूस ही नहीं हुआ, कि मेरा अपमान हुआ है। क्योंकि शंभू नाथ तो मान अपमान से हैं ही कौसों दूर।

वैसे भी भगवान शंकर, मैना के द्वारा पाये जाने वाले सम्मान के लिए

भगवान शंकर को देखते ही मैना क्यों घबरा गई?

भगवान शंकर, आज की तिथि में केवल भगवान ही नहीं हैं, अपितु मैना के जमाई भी हैं। किसी दूल्हे के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार हो जाये, तो निश्चित ही दूल्हा उस चौखट से वापिस मुड़ खड़ा होता है। किंतु भगवान शंकर को देखिए, तो वे रती भर भी क्रोधित नहीं होते।

संसार में अपमान किसी को नहीं

भाता। सम्मान की प्राप्ति न हो, तो एक बार के लिए चल भी जाता है, किंतु उसी सम्मान जगह, अपमान मिल जाए, यह किसी को गवारा नहीं होता। सोच कर देखिए, एक साधारण व्यक्ति को जब यह स्वीकार नहीं, तो वह व्यवहार हम ईश्वर के लिए कैसे सोच सकते हैं ? निश्चित ही हमें नहीं सोचना चाहिए। किंतु जब भगवान शंकर अपनी बारात लेकर हिमाचल के महलों में पहुँचे, तो क्या हिमवासियों ने उनका सम्मान किया ?

भगवान शंकर, जो कि इस सृष्टि के प्रथम योगी हैं। महान तपस्वी व करुणा के सागर हैं। जिनका सम्मान स्वयं विष्णु व ब्रह्मा जी करते हैं। उनका सम्मान हिमाचल के साधारण

वासी भी करने को तैयार नहीं। मैना, जो कि भगवान शंकर की सासु जी के नाते उनका स्वागत करने आई हैं, वे आरती की थाली लेकर उनके समक्ष तो जाती हैं, किंतु भोलेनाथ को देखते ही भय से काँपने लगती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं।

कंचन थार सोह बर पानी।

परिजन चली हरहि हरषानी।।

बिकट बेष रुद्रहि बर देखा।

अबलह उर भय भयउ विसेषा।।

भागि भवन पैठी अति त्रसा।

गए महसु जहाँ जनवासा।।

मैना हदयं भयउ दुखु भारी।

लीन्ही बोली गिरीसुकुमारी।।

भगवान शंकर के भयंकर वेष को देखते ही मैना घबरा गई। आरती

थाली थाली वहीं उलट पुलट गई। उसकी आँखें पलट गई। माथा पसीने से भीग गया। उसके रोम-रोम में भय की लहर दौड़ गई। कहाँ तो मैना का हृदय हर्ष से ओत प्रोत होना था, कहाँ वह महान शोक में डूब गई। उन्होंने दूल्हे के स्वागत में जो भी रीति संस्कारों का निर्वाह करना था, वे सब भूल गई। उन्हें भान ही न रहा, कि वे अपने जमाई राजा का शुभाम्मन करने आई हैं। वे ऐसी भयभीत हुई, कि हाथ से आरती का थाल ही गिर गया। व उल्टे पैर वापिस दौड़ पड़ी। इस आयु में भी मैना ऐसी दौड़ी, मानों वे कोई धावक हैं। पता ही न चला, कि रास्ते में कोई ईंट रोड़ा भी है या नहीं। बस यही था, कि

किसी न किसी प्रंगल से प्राणों की रक्षा की जाये। इधर भगवान शंकर, आज की तिथि में केवल भगवान ही नहीं हैं, अपितु मैना के जमाई भी हैं। किसी दूल्हे के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार हो जाये, तो निश्चित ही दूल्हा उस चौखट से वापिस मुड़ दूल्हा होता है। किंतु भगवान शंकर को देखिए, तो वे रती भर भी क्रोधित नहीं होते। वे स्वयं ही उस दिशा में बढ़ जाते हैं, जहाँ जनवास में उनके ठहरने का प्रबंध हुआ था। उन्हें तो महसूस ही नहीं हुआ, कि मेरा अपमान हुआ है। क्योंकि शंभू नाथ तो मान अपमान से हैं ही कौसों दूर।

वैसे भी भगवान शंकर, मैना के द्वारा पाये जाने वाले सम्मान के

डॉ.अशोक तिवारी को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार



मुंबई (उत्तरशक्ति)। देश के जाने-माने व्यवसाई, वैज्ञानिक, कवि एवं मंच संचालक डॉ. अशोक तिवारी का चयन अमेरिकन सोसायटी आफ मैटेरियल्स (अस्ट) के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एलन रे पुट्टनम सर्विस अवार्ड 2026 के लिए किया गया है। वह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। डॉ अशोक तिवारी

अस्ट इंटरनेशनल की भारत इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में अस्ट की भारत इकाई ने एडवांस मैटेरियल्स फॉर स्पेस तथा एडवांस मैटेरियल्स फॉर डिफेंस आयोजित कर चुका है। साथ ही मटेरियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि भारत के अस्ट द्वारा आयोजित किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। डॉ. तिवारी को यह अवार्ड 29 सितंबर, 2026 को कनाडा के क्यूबेक शहर में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया जाएगा।

बरसात के मौसम में बढ़ती हुई मानसूनी बीमारियों की रोकथाम के लिए मनपा अस्पतालों को सुसज्ज किए जाने की मांग

मुंबई (उत्तरशक्ति)। एक सप्ताह पूर्व मुंबई में भारी बारिश हुई। जिससे अनेक जगहों पर बरसती पानी का जमाव हो गया। इस कारण बरसात के इस मौसम में मुंबई में मानसूनी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। विशेषकर मुंबई की अनेक झोपड़पट्टियों में डेंगू, मलेरिया टायफाइड, स्वाइन फ्लू के अलावा कोरोना का भी प्रकोप बढ़ रहा है। जून के शुरूआती महीने में डेंगू, मलेरिया स्वाइन फ्लू, डायरिया से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज पाए गए। इसी तरह दूषित पानी के कारण गैस्ट्रो का भी प्रकोप बढ़ा है। जिसके कारण झोपड़पट्टियों में बीमारियों के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए राकांपा चांदीवली तालुका के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने मुंबई मनपा आयुक्त से पश्चिमी उपनगर के कूपर , पूर्वी उपनगर के शताब्दी, घाटकोपर के राजावाड़ी और सायन अस्पताल में बीमारियों की रोकथाम के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने की मांग की है।

बता दें मुंबई की अनेक झोपड़पट्टियों में बरसात के इस मौसम में मानसूनी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। इस कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके अलावा कोरोना भी पांव पसार रहा है विशेष रूप से जलजमाव और दूषित पानी की सप्लाई से गैस्ट्रो, टायफाइड, हैजा पीलिया जैसी बीमारियों तेजी से बढ़ रही है। मनपा आयुक्त को लिखे पत्र में सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले दो साल से मुंबई मनपा का कामकाज बगैर नगरसेवकों के चलया जा रहा है। ऐसे में पूर्वी उपनगर के अंतर्गत आने वाली गोवंडी के कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ नगर, मानखुर्द मंडला, शिवाजी नगर बेगनवाड़ी, रफी नगर डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर, सेंबर वासीनाका, माहुल गांव भारत नगर, अयोध्या नगर , साकीनाका खाड़ी क्रमांक तीन, खैरानी रोड, तुंग में साफ सफाई न होने से बढ़ती हुई गंदगी और कचरे के ढेर से बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बारिश के चलते मानसूनी बीमारी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुु निया जैसी बीमारियां भी फैल रही है। इस कारण मनपा अस्पतालों में मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जिसके कारण मनपा आयुक्त से सुरेंद्र सिंह ने के.एम, सायन, देवनार के शताब्दी नगर और घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा खात की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग से विभाग बनाने की मांग की है।

अवैध गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स के कारण किशोर और युवा वर्ग खतरे में: कट्स इंटरनेशनल

मुंबई। भारत में तेजी से बढ़ते अवैध सट्टेबाजी एवं गैंबलिंग मार्केट से किशोरों एवं युवाओं जैसे संवेदनशील वर्ग पर उल्लेखनीय खतरा मंडरा रहा है। ग्राहकों की संप्रभुता पर केंद्रित पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक कट्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इन अवैध प्लेटफॉर्म पर सालाना करीब 100 अरब डॉलर का डिपोजिट होता है। रिपोर्ट में इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इससे यह सामने आया है कि अवैध ऑनलाइन गैंबलिंग से उपभोक्ताओं की सुरक्षा, वित्तीय अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। समस्या की गंभीरता को रिपोर्ट के इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के बीच 40 मिनर साइट्स के माध्यम से टॉप 15 अवैध गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स पर 5.4 अरब से ज्यादा विजिट्स देखने को मिलीं। 1एक्सबेट, पेरीमैच, स्टेक, फेयरप्ले और बैटरीबेट जैसे टॉप प्लेटफॉर्म पर लगातार बड़ा ट्रैफिक एवं यूजर्स की पहुंच देखने को मिल रही है। मार्च, 2025 में पेरीमैच के ट्रैफिक शेयर ने अमेजन डॉट इन, विकीपीडिया डॉट ओआरजी, गूगल डॉट को डॉट इन, एक्स डॉट कॉम, हॉटस्टार डॉट डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, लिंकडइन डॉट कॉम, कोरा डॉट कॉम और रेंटिड डॉट डॉट कॉम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स को भी पीछे छोड़ दिया था। कट्स के संस्थापक एवं महासचिव प्रदीप मेहता ने रिपोर्ट की लेकर कहा, अवैध गैंबलिंग ऑपरेटर्स बहुत व्यवस्थित तरीके से भारत के विज्ञापन एवं पैमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रहे हैं और करोड़ों रुपये देश से बाहर पहुंचा रहे हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हुआ है और भारतीय उपभोक्ताओं को भी बड़ा नुकसान है।

मेहता ने आगे कहा, नीतियों के स्तर पर कमी को लेकर इस रिपोर्ट के विश्लेषण से परेशान करने वाला तथ्य सामने आया है कि जहां एक ओर बहुत से देश अवैध गैंबलिंग पर सख्त कदम उठा रहे हैं और इस दिशा में बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी कर रहे हैं, वहीं भारत में इससे बचाव के लिए सामान्य व्यवस्था भी नहीं है। नियामकीय स्तर पर तत्काल कदम उठाए बिना ये प्लेटफॉर्म्स संवेदनशील यूजर्स को निशाना बनाते रहेंगे। भारतीय यूजर्स की सुरक्षा एवं हमारे डिजिटल इकोसिस्टम की अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें तत्काल कदम उठाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अवैध प्लेटफॉर्म्स का आकर्षण इनकी आसान पहुंच और इनके इमर्सिव एवं हाई रिस्क एक्सपीरियंस में छिपा है। स्टेक एवं 1एक्सबेट जैसे अवैध प्लेटफॉर्म साइकोलॉजिकल डिजाइन तकनीक का प्रयोग करते हैं और अक्सर ज्यादा रिस्क वाली सट्टेबाजी का मौका देते हैं, जिससे रोमांच बढ़ता है। इस तरह का माहौल अक्सर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारण उनके लिए गैंबलिंग से ज्यादा नुकसान का खतरा भी बढ़ जाता है। अवैध गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर नो योर कस्टमर (केवाईसी) और उम्र को प्रमाणित करने जैसे सुरक्षा के सामान्य कदम भी नहीं उठाए जाते हैं। इससे बच्चे भी आसानी से गैंबलिंग तक पहुंच जाते हैं। इससे न केवल खतरनाक कंटेंट तक उनकी पहुंच हो जाती है, बल्कि कम उम्र में ही बच्चे अवैध गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित भी होने लगते हैं। विदेश में बैठे कई ऑपरेटर्स जैसे पेरीमैच, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट जैसी रणनीति अपनाते हैं, जिससे बच्चों के लिए इनका प्रयोग और भी आसान हो जाता है।

सोलापुर के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पूर्व मंत्री सुभाष देशमुख के मार्गदर्शन में शिष्टमंडल की दुबई यात्रा

सोलापुर / मुंबई (उत्तरशक्ति)। सोलापुर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायक व पूर्व वस्त्र उद्योग मंत्री सुभाष देशमुख के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने हाल ही में दुबई का दौरा किया। यह यात्रा सोलापुर सोशल फाउंडेशन और उद्यम फाउंडेशन, सोलापुर विश्वविद्यालय की पहल पर आयोजित की गई। सोलापुर को अंतरराष्ट्रीय ह्यूनिफॉर्म हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह दौरा एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। महाराष्ट्र के ऐसे शिष्टमंडल का दुबई जाना यह पहली बार है और इसमें यूनिफॉर्म गारमेंट, चादर, टॉवेल, आईटी क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, कृषि उत्पादन, बचत समूहों के उत्पादों जैसे विभिन्न क्षेत्रों

के उद्योग प्रतिनिधियों का समावेश था.शिष्टमंडल का उद्देश्य था कि सोलापुर के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाई जाए और स्थानीय उद्योगों का गुणवत्तापूर्ण विकास हो। इस दौरे के दौरान डे टू डे स्टोर्स, बिगमार्ट, हाइपरमार्केट, चिटग्राम फूड मार्केट जैसे 30 से अधिक अग्रणी उद्यमों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने इस यात्रा के आयोजन के लिए विधायक सुभाष देशमुख की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व के कारण ही यह संभव हुआ। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र से विभिन्न क्षेत्रों जैसे यूनिफॉर्म, गारमेंट, टॉवेल, आईटी, साइबर सुरक्षा, कृषि उत्पाद और बचत समूहों के उद्यमी

अपहृत बच्ची 24 घंटे के अंदर नवी मुंबई से बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार

मुंबई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित पनवेल रेलवे स्टेशन के बाहर से अगवा की गई तीन माह की बच्ची को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल तलाश लिया और इस घटना के संबंध में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने रिविार को यह जानकारी दी। पनवेल शहर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नितिन ठाकरे ने बताया कि शुक्रवार दोपहर तीन बजे से साढ़े तीन बजे के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची को उस समय अगवा कर लिया जब वह अपनी मां के साथ स्टेशन के बाहर थी।

सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्ची की तलाश और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पांच टीम गठित कीं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जिसमें

एक महिला को बच्ची को लेकर पुणे जाने वाली ट्रेन में सवार होते हुए देखा गया।

इसके बाद पुलिस ने करजत, लोनावला, दौण्ड और पुणे के अन्य स्थानों पर टीम रवाना कीं। बाद में पुलिस को पता चला कि संदिग्ध महिला लोनावला से वापस पनवेल लौट आई है। शनिवार को पुलिस ने कर्लंबोली अग्निशमन केंद्र के पास महिला को बच्ची के साथ देखा और तुरंत उसे पकड़ लिया।

अधिकारी ने बताया कि बच्ची को सकुशल उसकी मां को सौंप दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान रोशनी विनोद वागेश्री (35) के रूप में हुई है जो पनवेल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित झोपड़पट्टी में रहती है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

तालाब के निजीकरण की साजिश के खिलाफ आमरण अनशन शुरू

मुंबई (उत्तरशक्ति)। कुलां के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज (शीतल) तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब के निजीकरण के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब बचाव समिति की अनेक से पिछले तीन दिनों से आमरण अनशन शुरू किया गया है। शीतल तालाब के निजीकरण के खिलाफ में शुरू किए गए इस अनशन को स्थानीय लोगों का जोरदार प्रतिसाद मिल रहा है।। बता दें कि पूर्वी उपनगर के शीतल तालाब का ऐतिहासिक महत्व है। इस तालाब में पिछले कई दशकों से गणेश विसर्जन और छठ पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ करता है। पिछले दिनों तालाब के किनारे दस फीट का सीमेंट का पोल खड़ा कर- के तालाब के समीप रहने वाले



हजारों लोगों के घरों का हवा तक बंद कर दिया गया। तालाब के निजीकरण होने से बचाने के लिए अनशन पर बैठे घनश्याम भापकर ने बताया कि हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की यहां कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब निजीकरण करने

की साजिश की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर तालाब है तो फिर सौंदर्यीकरण के लिए शीतल तालाब के नाम से टेंडर क्यों निकाला गया। इन सभी मुद्दों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब बचाव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। रविवार को चांदीवली तालुका राकांपा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने अनशनकारियों से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि यदि दो सप्ताह के भीतर तालाब बचाने के लिए अनशन कर रहे लोगों को न्याय न मिला तो राकांपा भी इस अनशन में उतरेगी।

महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक संगठन की ओर से स्वास्थ्य शिविर



कल्याण (उत्तरशक्ति)। केडीएमसी के भूतपूर्व स्थायी समिति सभापति स्वर्गीय रमेश तरे की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति कल्याण पूर्व में महाराष्ट्र रिक्शा

चालक-मालक संगठन की ओर से विठ्ठलवाड़ी स्टेशन परिसर में भव्य स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। संगठन के विठ्ठलवाड़ी पूर्व विभाग के अध्यक्ष

और पूर्व उपमहापौर विक्रम रमेश तरे, कार्यध्यक्ष मयूरेश तरे तथा पूर्व नगरसेविका मोनाली तरे की पहल पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में रिक्शा चालकों के साथ-साथ रेल यात्रियों ने भी शिविर का लाभ लिया। जहां बीपी, शुगर, आंखों की जांच की गई। खड़कपाड़ा, कल्याण पश्चिम में स्थित ऐस एनएक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप महानजन और उनकी टीम ने नागरिकों की मेडिकल जांच की। इस मौके पर महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक सेना के शिवाजी गायकवाड़, आनंद गांगुरडे, महेंद्रकुमार यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जांच की। इस मौके पर महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक सेना के शिवाजी गायकवाड़, आनंद गांगुरडे, महेंद्रकुमार यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जांच की। इस मौके पर महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक सेना के शिवाजी गायकवाड़, आनंद गांगुरडे, महेंद्रकुमार यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जांच की। इस मौके पर महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक सेना के शिवाजी गायकवाड़, आनंद गांगुरडे, महेंद्रकुमार यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जांच की। इस मौके पर महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक सेना के शिवाजी गायकवाड़, आनंद गांगुरडे, महेंद्रकुमार यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जांच की। इस मौके पर महाराष्ट्र रिक्शा चालक-मालक सेना के शिवाजी गायकवाड़, आनंद गांगुरडे, महेंद्रकुमार यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सोलापुर सोशल फाउंडेशन और उद्यम फाउंडेशन सोलापुर विश्वविद्यालय की पहल पर दुबई यात्रा आयोजित



दुबई यात्रा पर गए। दुबई के 260 से अधिक कॉलेजों के छात्रों के

यूनिफॉर्म की आपूर्ति में सोलापुर की भागीदारी पर भी गंभीर विचार-विमर्श

हुआ। अल अदिल ट्रेडिंग के अध्यक्ष धनंजय दातार ने सोलापुर के छात्र

विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के साथ बैठक संपन्न



मुंबई-वडोदरा महामार्ग परियोजनाओं से प्रभावित नागरिकों की समस्याएं उजागर कीं और अधिकारियों को उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराया।

मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग टल्ल-48 पर चल रहे व्हाइट टॉपिंग कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए, वर्षा ऋतु में जलभराव और बढ़ते हादसों पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर एनएचआई परियोजना

संचालक सुहास चिटणीस ने कार्य की गुणवत्ता सुधारने और आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त एमआरवीसी और डीएफसीसी को निर्देश दिए गए कि वे निर्माण स्थलों, विशेषकर बोईसर-कालकरपाड़ा, पंचाली, केलवे रोड, रोडे, डहाणू कसारा और जुन्नरपाड़ा के फवर्ड क्षेत्रों में बारिश के कारण जलभराव को समस्या न हो, इसके लिए पुख्ता

निविदा रद्द करने पर आदित्य ने शिंदे पर साधा निशाना

मुंबई। महाराष्ट्र की एंजेसी एएमएमआरडीए द्वारा ठाणे में दो बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया रद्द किए जाने का निर्णय लेने के बाद शिवसेना (उबाठा) ने शनिवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पद से हटाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के निर्णय के मद्देनजर राज्य में सभी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की न्यायिक जांच कराने की मांग की और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

एएमएमआरडीए के अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री शिंदे हैं। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या आयकर विभाग को शिंदे के खिलाफ जांच का आदेश देना चाहिए। दूसरी ओर, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन

वीडियो पत्रकार के साथ मारपीट, चार लोग गिरफ्तार



मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के प्रभादेवी इलाके में एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के वीडियो पत्रकार पर हमला करने के सिलसिले में शनिवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पत्रकार अनिल शिंदे दोपहर में लोअर परेल स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। अनिल अधिकारी ने कहा, जब पुलिस पैदल जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच

बहस शुरू हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने एक डंडे से शिंदे के सिर पर वार किया। इसके बाद, आरोपी अपने तीन साथियों के साथ वापस आया और शिंदे की पिटाई की। अधिकारी ने बताया कि शिंदे द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देने के बाद एन एम जोशी मार्ग पुलिस थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले गई। उन्होंने कहा, घटना के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की विस्तृत जांच जारी है।

और पारंपरिक उत्पादों को दुबई के बाजार में लाने का आश्वासन दिया और सोलापुर की सांस्कृतिक धरोहर व उद्यमशीलता की प्रशंसा की। शरजार्ह स्थित रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क की भी यात्रा कर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसरों का अध्ययन किया गया।

शिष्टमंडल में सुभाष बापू देशमुख (संस्थापक अध्यक्ष, सोलापुर सोशल फाउंडेशन), अमित जैन (निदेशक, सोलापुर गारमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन), डॉ. राजेश गुरानी (सईओ, उद्यम फाउंडेशन), विजय पाटील (मुख्य समन्वयक), और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े उद्यमी जैसे प्रकाश पवार, प्रशांत राठी, देव जैन, श्रीनिवास बासूतकर, यश रंगरेज, सागर गड्डम, आनंद झाड़ आदि शामिल थे।

व्यवस्था सुनिश्चित करें। बैठक में सभी विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ और समाधान की दिशा में ठोस निर्णय लिए गए। इस बैठक में सहायक जिलाधिकारी डहाणू विशाल खत्री, सहायक जिलाधिकारी जव्हार अपूर्वा बसूर, भू-संपादन समन्वयक उपजिलाधिकारी महेश सागर, पुनर्वास उपजिलाधिकारी तेजस चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी वाडा संदीप चव्हाण, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी पालघर रविंद्र राजपुर, जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख नरेंद्र पाटील, देहर्जे व लेंडी परियोजना के कार्यकारी अभियंता दिनेश शेवाले, अधीक्षक अभियंता अमोल फुडे, सहायक संचालक नगररचना भाग्यश्री धवलसंक, डीएफसीसी और एमआरवीसी तथा बुलेट ट्रेन के अधिकारी उपस्थित थे।



सपकाल ने राज्य में सभी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की न्यायिक जांच की मांग की और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि घोड़बंदर-भयंदर सुरंग परियोजना और मुंबई एलिफेंट्स रोड परियोजना में 3,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। एएमएमआरडीए ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह गायमुचा-घोड़बंदर-भायंदर परियोजना से

जुड़ी दो निविदाओं को रद्द कर रहा है और हत्यापक जनहित की रक्षा के लिए एन एफ सिरे से बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

उच्चतम न्यायालय अवसंरचना निर्माण से जुड़ी दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसे परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए अयोग्य ठहराने के एएमएमआरडीए के फैसले को चुनौती दी गई है।

पालघर हत्याकांड का आरोपी 24 साल बाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

मुंबई। महाराष्ट्र के पालघर जिले में हत्या के एक मामले में पिछले 24 साल से फतार आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपरधरा) मदन बल्लाल ने बताया कि आरोपी की पहचान मामू उर्फ छोटे उर्फ बाबून ओमप्रकाश श्रीसाहूनी दिवाकर (50) के रूप में हुई है और उसे उत्तर प्रदेश के कानून्पुर से पकड़ा गया। वह मोहरम अली मोहम्मद इब्राहिम अली (46) नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित था। 14 जनवरी 2001 को विरार इलाके में धारदार हथियार से अली के पेट पर वार किया गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। बल्लाल ने बताया कि इसके बाद विरार पुलिस ने हारून अली मुस्तकीन अली सैयद और मामू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था। अपराध के पीछे का मकसद बकाया किराया न चुकाने को लेकर विवाद था। उन्होंने बताया कि मोहरम अली आरोपी के ऑटोरिक्षा में अकसर यात्रा करता था लेकिन कथित तौर पर किराया नहीं देता था।

स्वामी: शरद फागुम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, ओरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोगोवां (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुद्रित एवं के-4, रुम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर यु समता सहकारी को. ऑ. हां. सांसाटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरगांव (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/20१8/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।

पत्राचार कार्यालय: मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रेड टर्मिनल, डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटफ हिल, वडाला मुंबई-37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

